



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019/कार्तिक 17, 1941

No. 359]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/KARTIKA 17, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

(पाटनरोधी जांच)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच – माननीय सेसटेट द्वारा दिनांक 17.06.2019 के आदेश के माध्यम से दिया गया रिमांड।

फा. सं. 15/06/2016-डीजीएडी.—जबकि समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) और माननीय सेसटेट के दिनांक 17.06.2019 के आदेश को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- जबकि उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयात के विरुद्ध 4 नवंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 39/1/99-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की और प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच परिणाम 6 अप्रैल, 2000 को जारी किए गए थे। अधिसूचना संख्या 76/2000-सीमा शुल्क द्वारा 23 मई, 2000 को अंतिम शुल्क लगाए गए थे। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 3 नवंबर, 2000 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2000 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 147/2000 द्वारा लगाए गए थे।

2. शुल्क लगाए जाने की समीक्षा समय-समय पर की गई है और प्राधिकारी द्वारा दूसरा निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 30 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/4/2010-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किया था। प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क दिनांक 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमा शुल्क द्वारा लगाया गया था।
3. पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप में विद्यमान निर्दिष्ट स्वरूप को नियत स्वरूप में बदलने और पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा में वृद्धि के अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता के आदेश पर की गई मध्यावधि समीक्षा के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/2/2013-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। पाटनरोधी शुल्क 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमा शुल्क के अनुसार 16 अगस्त, 2016 तक लागू था और शुल्क की मात्रा दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/2/2013-डीजीएडी के अनुसार संशोधित की गई थी।
4. और जबकि, मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे यहां बाद में संबद्ध सामान भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां बाद में प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष वर्तमान मामले में आवेदन पत्र दायर किया और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।
5. और जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 19 जुलाई, 2017 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।
6. और जबकि, घरेलू उद्योग ने दिनांक 19 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 25 अगस्त, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 40/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) को चुनौती देते हुए माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सेसटेट), प्रधान बेंच, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की। घरेलू उद्योग की शिकायत यह है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत (एनआईपी) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों से असंगत और कम है।
7. और जबकि, माननीय सेसटेट ने हितबद्ध पक्षकारों को व्यापक रूप से सुनने के बाद 17 जून, 2019 को एक आदेश जारी किया जिसमें अधिकरण ने इस आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एनआईपी पुनः निर्धारित करने के लिए मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजकर अपील की अनुमति दी।

सेसटेट ने अपने आदेश के पैरा 29 में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि एनआईपी के निर्धारण के लिए सिद्धांतों की धारा 4(vi) में यह प्रावधान है कि सामान्य व्यय उपयुक्त एवं वैज्ञानिक आधार पर संविभाजित किए जाने चाहिए जिसमें एक "उत्पादन गुणवत्ता" है, तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य व्यय "बिक्री मूल्य" के आधार पर निर्धारित किए हैं। तर्क यह है कि "उत्पादन गुणवत्ता" के आधार पर सामान्य व्यय का संविभाजन ही उपयुक्त एवं वैज्ञानिक नहीं है **बल्कि इसे घरेलू उत्पादकों द्वारा भी निरंतर लागू किया गया है**, परंतु प्रकटन विवरण में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है कि एनआईपी "उत्पादन गुणवत्ता" के आधार पर निर्धारित क्यों नहीं किया गया। यह भी अनुरोध किया गया है कि यहां तक कि यद्यपि अपीलकर्ता ने प्रकटन विवरण पर प्रस्तुत टिप्पणियों में विस्तार से उल्लेख किया था कि सामान्य व्यय "उत्पादन गुणवत्ता" के आधार पर क्यों निकाले जाने चाहिए और "बिक्री मूल्य" के आधार पर क्यों नहीं, फिर भी "बिक्री मूल्य" पर सामान्य व्यय निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निकाले गये जांच परिणाम में कोई कारण नहीं दिया गया है।

सेसटेट ने अपने आदेश के पैरा 41 में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में केवल यह अपेक्षित नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कारण बताने के लिए पक्षकार को अवसर प्रदान करें बल्कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश में निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए कारण भी दिए जाने चाहिए और इन दोनों बातों के किसी भी उल्लंघन से आदेश रद्द हो सकता है। वर्तमान मामले में न तो प्रकटन विवरण में अपीलकर्ता को कोई सूचना दी गई थी और न ही अंतिम जांच परिणाम कोई बताते हैं।

माननीय सेसटेट ने दिनांक 17.06.2019 के अंतिम आदेश सं. एडी/ए/50774/2019-सीयू (डीबी) (2018 की पाटनरोधी अपील सं. 50401) द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिया:

"अतः एनआईपी के निर्धारण के संबंध में दिनांक 19 जुलाई, 2017 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम संधारित नहीं किए जा सकते और अलग किए जाते हैं। इस प्रकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना में शुल्क लगाए जाने की मात्रा सही नहीं है। अतः यह मामला इस आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एनआईपी पुनः निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जाता है। तथापि, दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना में निहित शुल्क लगाया जाना वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नई अधिसूचना जारी किए जाने तक जारी रहेगा। तदनुसार, इस अपील की ऊपर दर्शाई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।"

ख. प्रक्रिया

8. नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (i) माननीय सेसटेट के आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी ने 22 अगस्त, 2019 को आयोजित मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त किए, उनसे उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- (ii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को 15 अक्टूबर, 2019 को अनिवार्य तथ्य प्रकट किए गए थे। 25 अक्टूबर, 2019 तक टिप्पणियां मांगी गई थीं। केवल घरेलू उद्योग ने जारी प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर कीं। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन विवरण प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (iii) इस दस्तावेज में "****" हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना को दर्शाती है।
- (iv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्य 15 अक्टूबर, 2019 को प्रकट किए गए थे। 25 अक्टूबर, 2019 तक टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (v) (विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग के क्षेत्र, जांच की अवधि, पाटन और क्षति मूल्यांकन से संबंधित अन्य सभी मानदंड समान हैं। ये जांच परिणाम केवल एन आई पी के निर्धारण तक ही सीमित हैं क्योंकि माननीय सेसटेट द्वारा रिमांड केवल एन आई पी के पुनर्निर्धारण के मुद्दे के संबंध में है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. निम्नलिखित घरेलू उद्योग से प्रतिक्रिया है।

- (i) वर्तमान मामले में सीमित मुद्दा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए व्यय के संविभाजन की उपयुक्तता और उसे रद्द करने तथा प्राधिकारी द्वारा दूसरा आधार अपनाने से संबंधित है।
- (ii) यह कि नियमावली में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए संविभाजन को रद्द कर सकते हैं – जब याचिकाकर्ता ने उसे निरंतर लागू न किया हो, जब वह वैज्ञानिक न हो, जब वह उपयुक्त न हो।

- (iii) इसके अतिरिक्त, उपयुक्तता और औचित्य की जांच तत्काल पूर्व वर्ष में तदनुसूची राशि के साथ तुलना करके की जा सकती है।
- (iv) मरम्मत एवं रख-रखाव, बीमा, दर एवं कर तथा बहिप्रवाह शोधन संयंत्र के संबंध में व्ययों के लिए प्रमुख लागत के अनुपात में संविभाजन पर पुनः विचार किया जाए।
- (v) मरम्मत और रख-रखाव व्यय व्यापक रूप से मशीन संचालन से संबंधित हैं, अतः मशीन के जीवनकाल, रख-रखाव संविदा जैसे कारक संगत हैं।
- (vi) यद्यपि, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट संयंत्र बहुत पुराने हैं और 1972 में स्थापित किए गए थे, तथापि, एमएचसीएल ठोस संयंत्र बहुत नया है और 2014-15 में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एसएनआई और एसएनए संयंत्र में संस्थापित मशीनों की संख्या एमएचसीएल संयंत्र में संस्थापित मशीनों की संख्या की तुलना में काफी अधिक है।
- (vii) मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय सीधे ही मशीनों द्वारा लिए गए स्थान के आनुपातिक हैं और एसएनआई/एसएनए द्वारा लिया गया स्थान एमएचसीएल संयंत्र की तुलना में काफी अधिक है।
- (viii) मरम्मत एवं रख-रखाव, बीमा, दरों एवं करों तथा बहिप्रवाह शोधन संयंत्र व्यय को प्रमुख लागत से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. विभिन्न देशों के विरुद्ध सोडियम नाइट्राइट के संबंध में बहुविध जांचें विगत में डीजीटीआर द्वारा की गई हैं। हाल ही में, **रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" के आयातों** के संबंध में जांच की गई थी जिसमें जांच की शुरुआत 19.12.2017 को की गई थी और जांच को रद्द करते हुए अंतिम जांच परिणाम 30.07.2018 को जारी किए गए थे।
11. यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों के विरुद्ध जांचों की दूसरी श्रृंखला है जिसमें मूल जांच की शुरुआत 02.11.2001 को की गई थी और प्राथमिक जांच परिणाम 01.02.2002 को जारी किए गए थे। अंतिम जांच परिणाम 28.10.2002 को जारी किए गए थे। दूसरी निर्णायक समीक्षा का अंतिम जांच परिणाम 12.05.2014 को जारी किया गया था। इस मामले में, मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) 19.12.2017 को शुरू की गई थी और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 08.08.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हुए 30.07.2018 को जारी किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि आबंटन के आधार के संदर्भ में एनआईपी संबंधी मुद्दे उपर्युक्त एमटीआर के दौरान भी उठाए गए थे। एमटीआर अंतिम जांच परिणाम दिनांक 30.07.2018 के पैरा 108(i) में निम्नलिखित पठित है:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में एनआईपी निर्धारण के लिए अपनाया गया सिद्धांत वही है, जैसा पूर्व जांचों में निरंतर अपनाया गया है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में काफी लागत अनुपात कच्ची सामग्री की लागत और यूटिलिटीयों की लागत का है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार वास्तविक के संबंध में माना गया है। यह भी शामिल किया जाए कि घरेलू उद्योग के पिछले कई वर्षों के लिए पाटनरोधी जांच के तहत कई उत्पाद हैं। यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों के संबंध में दिनांक 12.05.2014 की अधिसूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जांच के दौरान यह नोटिस किया गया था कि कंपनी ने दो संयुक्त उत्पादों यथा सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के लिए आबंटन की भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपनाई थीं। चूंकि, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के तहत अपेक्षित संगत पद्धति अपनाई थी, अतः दोनों उत्पादों अर्थात् सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के संबंध में तभी से अन्य लागतों के आबंटन के लिए एक समान सिद्धांत लागू किया गया है। उसके बाद सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कंपनी ने इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की।

12. **याचिकाकर्ता कंपनी का दूसरा उत्पाद अर्थात् "सोडियम नाइट्रेट" है जो भी यूरोपीय संघ, चीन जन. गण., यूक्रेन और कोरिया गणराज्य से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के अधीन है।** जांच की पहली शुरुआत 05.06.2013 को की गई थी और प्राथमिक जांच परिणाम 06.01.2014 को जारी किए गए थे। अंतिम जांच परिणाम 12.11.2014 को जारी किए गए थे। **यही सिद्धांत इस मामले में भी अपनाए गए थे।**

13. **वर्तमान मामला चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" उत्पाद के संदर्भ में तीसरी निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम से संबंधित है जो दिनांक 19.07.2017 को जारी किया गया था। यह मामला 04.11.1999 को शुरू किया गया था और प्राथमिक जांच परिणाम 06.04.2000 को जारी किया गया था। अंतिम जांच परिणाम 03.11.2000 को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, दूसरी निर्णायक समीक्षा के मामले में अंतिम जांच परिणाम 30.06.2011 को जारी किया गया था। उसके बाद, 18.10.2013 को एमटीआर शुरू की गई थी और अंतिम जांच परिणाम 15.10.2014 को जारी किया गया था। तीसरी निर्णायक समीक्षा 27.07.2016 को शुरू की गई थी और अंतिम जांच परिणाम 19.07.2017 को जारी किया गया था। यही सिद्धांत इस मामले में भी निरंतर अपनाये गये हैं, जैसा कि पूर्व में अपनाये गए थे।**

14. सेसटेट आदेश का पैरा 8 यह दर्शाता है कि नाइट्राइट संयंत्र निम्नलिखित रसायनों का उत्पादन कर रहा है:

क्रम सं.	उत्पाद	जांच की अवधि के दौरान प्रति मी. टन बिक्री कीमत (रुपये में)
(i)	सोडियम नाइट्राइट	***
(ii)	सोडियम नाइट्रेट	***
(iii)	नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड	***
(iv)	पौटेशियम नाइट्रेट	***
(v)	एमएएचसीएल	***

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विभिन्न रसायनों की प्रति यूनिट बिक्री कीमतों में काफी अंतर हैं और कंपनी मूल रूप से यह तर्क दे रही है कि लागतों अथवा कीमतों पर ध्यान न देते हुए सभी रसायनों का ऊपरी खर्चों की उसी राशि का संविभाजन किया जाना चाहिए।

15. अनुबंध-3 की धारा 4(vi) में निम्नलिखित पठित है:

"उत्पाद में अभिज्ञात सीमा तक व्यय सीधे ही आबंटित किए जाने होते हैं और सामान्य व्यय अथवा फैक्ट्री, प्रशासनिक और बिक्री के ऊपरी खर्चों को घरेलू उत्पादकों द्वारा सतत रूप से लागू किए गए अनुसार मशीन घंटों, वेसेल, ऑक्युपेंसी घंटों, प्रत्यक्ष श्रम घंटों, उत्पादन मात्रा, बिक्री मूल्य जैसे उपयुक्त एवं वैज्ञानिक आधार पर संविभाजित किया जाए तथा जांच की अवधि के लिए दावा किए गए विभिन्न खर्चों की उपयुक्तता और औचित्य की जांच की जाए तथा तत्काल पूर्व वर्ष में तदनुसारी राशि से तुलना कर उसकी जांच की जाए।"

16. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य लागतों की उपयुक्तता सुनिश्चित करना है और औचित्य के आधार पर "बिक्री मूल्य" सिद्धांत का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है जिसे इस मामले में डीजीटीआर द्वारा निरंतर अपनाया जाना उल्लिखित किया गया है।
17. अपीलकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद (सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड, पौटेशियम नाइट्रेट और एमएसीएचएल) भिन्न प्रकृति के हैं और उनकी भिन्न कीमत है तथा उसी परिसर में विभिन्न संयंत्रों पर विनिर्मित किए जाते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया भी विभिन्न उत्पादों के लिए भिन्न है, अतः "उत्पादन अनुपात" जैसी विशेष पद्धति पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।
18. भौतिक यूनिटों की पद्धति की दूसरी कमी यह है कि यह मुख्य उत्पादों की भौतिक यूनिटों की मात्रा का ही उनके मूल्य पर ध्यान न देते हुए संयुक्त लागतों में फैलाने के लिए प्रयोग करती है। यह विशिष्ट रूप से उप-उत्पादों और अन्य विविध आय की अनदेखी करेगी जिस पर कोई लागत आबंटित नहीं की जाएगी।
19. अप्रत्यक्ष श्रम लागत, जो प्रशासनिक ऊपरी खर्चों का लगभग *** प्रतिशत है, घरेलू उद्योग द्वारा और डीजीटीआर द्वारा स्वीकृत दोनों कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संविभाजित की गई है। निगम के ऊपरी खर्चों, जो प्रशासनिक ऊपरी खर्चों के लगभग *** प्रतिशत हैं, विभिन्न प्रभागों में कंपनी द्वारा खुद ही कारोबार के आधार पर आबंटित किए गए प्रतीत होते हैं। अतः इसका कोई कारण नहीं है कि विभिन्न उत्पादों के लिए प्रभाग के अंतर्गत वही पद्धति क्यों नहीं अपनाई जानी चाहिए।

20. एनआईपी की समीक्षा करते समय विनिर्माण के ऊपरी खर्चों, प्रशासनिक खर्चों, बिक्री खर्चों के आधार सही पाए गए हैं, तथापि, प्राथमिक लागत के निर्धारण के समय गलती से प्राथमिक पैकिंग, प्रत्यक्ष लेबल लागत और पानी की लागत जैसी लागत प्राथमिक लागत में शामिल नहीं की गई थी, अब उसे ठीक कर लिया गया है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

21. प्रकटन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- I. घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर (क) मरम्मत एवं रख-रखाव, (ख) बीमा, (ग) दर और कर तथा (घ) बहिर्प्रवाह शोधन संयंत्र के निमित्त संविभाजन के आधार के परिवर्तन के संबंध में विचार नहीं किया गया है।
 - II. एनआईपी में संशोधन प्राथमिक लागत के निर्धारण के लिए प्राथमिक पैकिंग, प्रत्यक्ष श्रम लागत और पानी की लागत जैसी लागत को शामिल करने के निमित्त ही किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता के अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है।
 - III. प्रकटन में सोडियम नाइट्राइट के विगत मामलों से संगतता के रूप में तर्क दिया गया है। तथापि, सांविधिक अपेक्षा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगतता नहीं है, परंतु घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई संगतता है। इस आधार पर संविभाजन पद्धति को रद्द करना कि उसे प्राधिकारी द्वारा निरंतर लागू किया गया है, कानून के अनुसार नहीं है।
 - IV. यह वास्तविक रूप से गलत है कि यह प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया सतत सिद्धांत है। प्राधिकारी ने मूल जांच में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को अपनाया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह मूल जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया सिद्धांत है, अतः समीक्षा जांच केवल नई अवधि के आंकड़ों के आधार पर एनआईपी के पुनः परिकलन की है। प्राधिकारी ने समीक्षा जांचों में एनआईपी के निर्धारण के लिए सिद्धांत को संशोधित नहीं किया है।
 - V. एक उपभोक्ता की मौजूदगी, कच्ची सामग्री की उच्च लागत जिससे उत्पाद की उच्च कीमत बनती है, याचिकाकर्ता के वैश्विक रूप से एकमात्र उत्पादक होना जिसकी उच्च कीमत है, आदि की यह निर्धारित करने में अनदेखी नहीं की जा सकती कि कारोबार अथवा उत्पादन क्या उपयुक्त आधार पर है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि मरम्मत और रख-रखाव, बीमा, बहिर्प्रवाह शोधन संयंत्र जैसे खर्च उत्पादन से सीधे ही संबद्ध हैं न कि कारोबार से।
 - VI. जहां तक इसका संबंध है कि "बिक्री मूल्य" के प्रयोग के संबंध में कोई अड़चन नहीं है, प्रकटन विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है कि उत्पादन अनुपयुक्त पद्धति है और कारोबार उपयुक्त पद्धति है। मरम्मत और रख-रखाव, बीमा, बहिर्प्रवाह शोधन संयंत्र और दर एवं कर जैसे विनिर्माण व्यय, जो सीधे ही उत्पाद के उत्पादन से संबंधित हैं और न कि उपयुक्त संविभाजन पद्धति के रूप में उत्पादन मूल्य से।
 - VII. प्राधिकारी ने उत्पादन को संविभाजन पद्धति के रूप में निरंतर लागू किया है। जहां भिन्न कीमत, उसी संयंत्र में विभिन्न संयंत्रों पर विनिर्मित, भिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं वाले भिन्न प्रकृति के भिन्न सामान हैं।
 - VIII. घरेलू उद्योग ने मरम्मत एवं रख-रखाव, बीमा, बहिर्प्रवाह शोधन संयंत्र और दर एवं कर, जो विनिर्माण व्यय हैं, जैसे व्यय आबंटित करने के लिए विवादित आबंटन पद्धति का प्रयोग किया है। निगम व्यय विनिर्माण व्यय नहीं है। विनिर्माण व्ययों को निगम व्ययों के साथ जोड़ना पूरी तरह से अनुपयुक्त पद्धति है।
 - IX. (क) मरम्मत एवं रख-रखाव, (ख) बीमा, (ग) दर एवं कर तथा (घ) बहिर्प्रवाह शोधन संयंत्र को कैसे उत्पादन के आधार पर आबंटित किया जाना चाहिए, इसका विस्तृत तर्क दिया गया है। तथापि, उसे रद्द कर दिया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. यह नोट किया जाता है कि इस मामले में प्रकटन पश्चात टिप्पणियां केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात कोई नए मुद्दे/टिप्पणियां दायर नहीं की गई हैं। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की पहले ही जांच कर ली है। इसके मद्देनजर, एनआईपी के पुनः निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की पुष्टि की जाती है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा एनआईपी पुनः निर्धारण के संबंध में जांच आयोजित की गई और जैसा कि पैरा 10-20 में उल्लिखित है।

निष्कर्ष

23. उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचना और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर तथा दिनांक 19.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी ने एनआईपी ***/- रुपये/मी. टन में संशोधित की।

सिफारिश

24. तदनुसार, प्राधिकारी ने सिफारिश की कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत आने वाले सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखा जाए। पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या 8 में उल्लिखित राशि होगी। यह पाटनरोधी शुल्क दिनांक 25.08.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) की तारीख से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	मापन इकाई	की मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834.1010	सोडियम नाइट्राइट	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	79.58	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	79.58	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	79.58	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

आगे की प्रक्रिया

25. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई भी अपील केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975, सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 8th November, 2019

(Anti-Dumping Investigation)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Sodium Nitrite” originating in or exported from China PR – remanded by Hon’ble CESTAT through Order dated 17.06.2019.

F.No. 15/06/2016-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules), and the Hon’ble CESTAT’s order dated 17.06.2019.

A. Background of the Case

- Whereas having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation against import of Sodium Nitrite originating in or exported from

China PR vide Notification No.39/1/99-DGAD on 4th November, 1999 and preliminary findings were issued by the Authority on 6th April, 2000. Provisional duties were imposed on 23rd May, 2000 vide notification no. 76/2000-Customs. The Authority notified final findings on 3rd November, 2000 recommending imposition of definitive duties on imports of Sodium Nitrite originating in and exported from China. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject country were imposed by the Department of Revenue vide Customs Notification No. 147/2000 dated 19th December, 2000

2. The imposition of duty has been reviewed from time to time and the second sunset review final finding was notified by the Authority vide Notification No. 15/4/2010 - DGAD dated 30th June, 2011 recommending continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 76/2011-Customs dated 17th August, 2011.
3. After the mid-term review conducted at the behest of the petitioner requesting for change in the form of antidumping duty from the existing benchmark form to fixed form and enhancement in the quantum of anti-dumping duties, the Authority notified final findings recommending change in the form of anti-dumping duty vide Notification No. 15/2/2013- DGAD dated 15th October 2014. The anti-dumping duty was in force up to 16th August 2016 in accordance with Notification No. 76/2011-Customs dated 17th August, 2011 and the quantum of duty was modified in accordance with Notification No. 15/2/2013-DGAD dated 15th October 2014.
4. And whereas, M/s. Deepak Nitrite Limited (hereinafter also referred to as “Petitioner” or “Applicant”) filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiating sunset review of the anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for extension of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
5. And whereas the Designated Authority issued Final Findings on 19th July, 2017 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of “Sodium Nitrite” originating in or exported from China PR and definite Anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No 40/2017-Customs (ADD) dated 25th August 2017.
6. And whereas domestic industry filed appeal before the Hon’ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi challenging the Final Findings dated 19th July, 2017 and the Customs Notification No 40/2017-Customs (ADD) dated 25th August 2017. The grievance of the domestic industry is that Non-Injurious Price (NIP) determined by the Authority is low and inconsistent with the principles laid down in Annexure III of AD Rules.
7. And whereas the Hon’ble CESTAT after extensively hearing the interested parties issued an order dated 17th June, 2019 wherein the Tribunal allowed the appeal by remitting the matter back to Designated Authority to re-determine the NIP, keeping in mind the observations made in this Order.

The CESTAT in para 29 of its order has stated as under:

*The grievance of the Appellant is that though clause 4(vi) of the principles for determination of NIP provides that the common expenses should be apportioned on a reasonable and scientific basis, one of which one is the ‘production quantity’, the designated authority has determined the common expenses on the basis of ‘sales value’. The contention is that not only is the apportionment of common expenses on “production quantity” basis a reasonable and scientific, **but it has also been applied consistently by the domestic producers** but the disclosure statement does not give any reason as to why NIP was not determined on ‘production quantity’ basis. It has also been urged that even though the Appellant had in the comments submitted to the disclosure statement, elaborately pointed out why the common expenses should be worked out on the basis of “production quantity” and not “sales value”, yet no reasons have been given in the final findings arrived at by the designated authority for determining the common expenses on ‘sales value’.*

The CESTAT in para 41 of its order has stated as under:

Thus, it is clear from the aforesaid decisions of the Supreme Court that the principles of natural justice not only require the designated authority to grant an opportunity to the party to show cause but the order passed by the designated authority should also give reasons for arriving at conclusions and any violation of these two facets can vitiate the order. In the present case, neither was any information supplied to the Appellant in the disclosure statement nor do the final findings give any reason.

Hon'ble CESTAT vide final order No. AD/A/50774/2019-CU (DB) dated 17.06.2019 (Anti-Dumping Appeal No. 50401 of 2018) inter-alia decided as under:

"The final findings of the designated authority notified in the Government Gazette dated 19 July 2017 in regard to the determination of NIP, therefore, cannot be sustained and are set aside. Thus, the extent of imposition of duty in the notification dated 25 August 2017 issued by the Ministry of Finance is not correct. The matter is, therefore, remitted to the designated authority to re-determine the NIP, keeping in mind the observations made in this Order. However, the imposition of duty contained in the notification dated 25 August 2017 shall continue till a fresh notification is issued in this regard by the Ministry of Finance. The Appeal is, accordingly, allowed to the extent indicated above".

B. Procedure

8. The procedure described below has been followed
 - (i) Pursuant to the order of the Hon'ble CESTAT, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a Oral Hearing held on 22nd August, 2019. The interested parties who presented their views orally at the time of Oral Hearing were requested to file written submissions of the views expressed by them orally. The Domestic Industry filed detailed submissions regarding their NIP claims.
 - (ii) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 15th October, 2019 to the concerned interested parties. Comments were requested by 25th October, 2019. Only domestic industry filed comments to the disclosure statement issued. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
 - (iii) '****' in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - (iv) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 15th October, 2019 to the concerned interested parties. Comments were requested by 25th October, 2019. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
 - (v) All other parameters related to the Product Under Consideration, scope of Domestic Industry, Period of Investigation, dumping and injury assessment remain the same. The findings are limited to determination of NIP only as the remand by Hon'ble CESTAT is on issue of redetermination of NIP only.

C. Submissions made by domestic industry

9. The following is the response from domestic industry.
 - (i) The limited issue in the present case concerns appropriateness of the apportionment of expenses done by the petitioner and rejection of the same and adoption of another basis by the Authority.
 - (ii) That the Rules provide that the Authority may reject the apportionment adopted by the petitioner only under following circumstances – when the petitioner has not applied the same consistently, when the same is not scientific, when the same is not reasonable.
 - (iii) Further, reasonableness and justification can be examined and scrutinised by comparing with the corresponding amounts in the immediate preceding year.
 - (iv) Apportionment in the ratio of prime cost for expenses regarding Repair and maintenance, Insurance, Rate and taxes and effluent treatment plant may be reconsidered-
 - (v) Repair and maintenance expenses largely pertain to machine running, hence the factors such as life of machine, maintenance contract etc. are relevant.
 - (vi) While sodium nitrite and sodium nitrate plant are very old and were set up in 1972, MAHCL solid plant is very new and was set up in 2014- 15. Further, the number of machines installed in SNI & SNA plant is much higher as compared number of machines installed in MAHCL plant.
 - (vii) Repair and maintenance expenses are directly proportional to the space consumed by the machinery and the space consumed by SNI/SNA plant is far higher as compared to MAHCL plant.
 - (viii) It would not be appropriate to link repairs and maintenance, insurance, rates and taxes, and effluent treatment plant expense to prime cost.

D. Examination by the Authority

10. Multiple investigations in respect of Sodium Nitrite against different countries have been conducted by DGTR in the past. Recently, investigation was conducted regarding **imports of "Sodium Nitrite" originating in or exported from Russia**, where initiation was done on 19/12/2017 and Final Finding terminating the investigation was issued on 30/07/2018.

11. There is another series of investigations against imports of **Sodium Nitrite originating in or exported from European Union**, where original initiation was done on 02/11/2001 and Preliminary findings was issued on 01/02/2002. The Final Finding was issued on 28/10/2002. The Final Finding of Second SSR was issued on 12/05/2014. A Mid-term review (MTR) was initiated on 19/12/2017 in this case, and Final Finding was issued on 30/07/2018 recommending continuation of anti-dumping duty imposed earlier vide Customs Notification dated 08.08.2014. It may be recalled that NIP related issues w.r.t. basis of allocation were raised during the aforesaid MTR also. Para 108 (i) of the MTR final finding dated 30.07.2018 reads as under:

The Authority notes that the methodology adopted for NIP determination in this investigation is the same as the one adopted consistently in previous investigations. It is noted that in the manufacture of PUC, significant proportion of costs consists of cost of raw material costs and utilities, which have been allowed on actuals as claimed by the DI. It may be added that the DI has number of products under anti-dumping investigation for last several years. It was noticed during the anti-dumping investigation on imports of Sodium Nitrite, originating in or exported from European Union vide notification No. 15/1009/2012-DGAD dated 12.05.2014 that the company had adopted different methods of allocation for two different joint products namely Sodium Nitrate and Sodium Nitrite. Since, the domestic industry had not adopted the consistent method as required under Annexure-III of AD Rules, a uniform methodology has been applied for allocation of others costs since then in respect of both products namely Sodium Nitrate and Sodium Nitrite. There has been no change in methodology thereafter.

The Company did not file any appeal against this order.

12. **The petitioner company has another product namely “Sodium Nitrate”,** which is also under anti-dumping duties against imports from European Union, China PR, Ukraine and Korea RP. The first initiation was done on 05/06/2013 and PF was issued on 06/01/2014. Final Findings were issued on 12/11/2014. The same **methodologies were followed in this case also.**
13. **The present case relates to the 3rd SSR final finding w.r.t product “Sodium Nitrite” originating in or exported from China PR, which was issued on 19/07/2017.** This case was initiated on 04/11/1999 and Preliminary findings was issued on 06/04/2000. The Final Finding was issued on 03/11/2000. Further, the Final Finding in case of second SSR was issued on 30/06/2011. Subsequently, MTR was initiated on 18/10/2013 and Final Finding was issued on 15/10/2014. **The third SSR was initiated on 27/07/2016 and the Final Finding was issued on 19/07/2017. The same methodologies have been consistently followed in this case also as were followed earlier.**

14. The Para 8 of CESTAT Order indicates that the Nitrite Plant is producing the following Chemicals:

S.No	Product	Sales Price Per MT during POI (In Rs.)
(i)	Sodium Nitrite	***
(ii)	Sodium Nitrate	***
(iii)	Nitro Sulphuric Acid	***
(iv)	Potassium Nitrate	***
(v)	MAHCL	***

It is clear from above that there are significant variations in the per unit sales prices of different chemicals and company is basically pleading that all chemicals irrespective of costs or prices should be apportioned the same amount of overheads;

15. Clause 4(vi) of Annexure-III reads as under:

*“The expenses to the extent identified to the product are to be directly allocated and common expenses or overheads classified under factory, administrative and selling overheads may be apportioned on reasonable and scientific basis such as machine hours, vessel occupancy hours, direct labour hours, **production quantity, sales value**, as applied consistently by domestic producers and the reasonableness and justification of various expenses claimed for the period of investigation may be examined and scrutinised by comparing with the corresponding amounts in the immediate preceding year.”*

16. It is clear from above that the objective is to ensure reasonability of costs and there is no bar on use of “sales value” method based on merit, which has been stated to be consistently followed by DGTR in this case;

17. The products (sodium nitrite, sodium nitrate, nitro sulphuric acid, potassium nitrate and MACHL) manufactured by the Appellant are of different nature and have different price and are manufactured at different plants in the same campus. The manufacturing processes are also different for different products. Therefore, considering the particular method such as 'production ratio' is not appropriate.
18. Another drawback of the physical units' method is that it uses the quantity of physical units of main products only to spread the joint costs regardless of their value. This typically would ignore by-products and other misc. income, which shall be allocated no costs.
19. Indirect Labour Cost, which constitutes almost *** % of Administration Overheads has been apportioned on the basis of number of employees both by the domestic industry and accepted by the DGTR. Corporate Overheads, which constitute almost *** % of Administration Overheads, seems to have been allocated on the basis of turnover by the company themselves amongst different divisions. Therefore, there is no reason as to why the same methodology should not be followed within the division for the various products.
20. While reviewing the NIP, the bases of apportionment of manufacturing overhead, administrative expenses, selling expenses have been found in order. However, at the time of determination of Prime cost, inadvertently, cost like Primary Packing, Direct labour cost and Water cost were not included in the prime cost, now same has been rectified.

E. Post Disclosure Comments

21. Domestic industry in response to the disclosure has made the following submissions –
 - (i) Submissions of the domestic industry have not been considered on change of basis of apportionment on accounts of (a) Repair and maintenance, (b) Insurance, (c) Rate and taxes and (d) Effluent treatment plant.
 - (ii) NIP has only been revised only on the account of inclusion of cost like primary packing, direct labor cost and water cost for determination of prime cost, thereby not considering the submissions of the Petitioner.
 - (iii) The Disclosure provides reasoning as consistency from past cases of Sodium Nitrite. However, statutory requirement is not consistency followed by the Authority, but consistency followed by the domestic industry. Rejection of apportionment method on the ground that it has been consistently applied by the Authority is not as per law.
 - (iv) It is factually incorrect that this is the consistent methodology applied by the Authority. The Authority had followed the methodology proposed by petitioner in the original investigations. Further, since it is the methodology followed by the Authority in the original investigations, the review investigation is only recalculation of NIP based on new period data. The Authority has not modified methodology for NIP determination in review investigations.
 - (v) Existence of one consumer, high cost of raw material leading to high price of the product, petitioner being the sole producer globally commanding high price, etc. cannot be ignored in deciding whether turnover or production is an appropriate basis. Further, petitioner submitted that expenses such as repair and maintenance, insurance, effluent treatment plant are directly linked to production, and not turnover.
 - (vi) As regards there is no bar on use of "sales value", the disclosure statement has not stated that production is an inappropriate method and turnover is an appropriate method. Manufacturing expenses like repair and maintenance, insurance, effluent treatment plant and rate and taxes which are directly related to the production of the product, and not value of production as an appropriate apportionment methods
 - (vii) The Authority has consistently applied production as an apportionment method where different goods of different nature, having different price, manufactured at different plants in the same campus, different manufacturing processes
 - (viii) The domestic industry has disputed allocation method used for allocating expenses like repair & maintenance, effluent treatment plant, insurance, and rates & taxes, which are manufacturing expenses. Corporate expenses are not manufacturing expenses. Linking manufacturing expenses with corporate expenses is a grossly inappropriate method.
 - (ix) Detailed reasoning as to how (a) Repair and maintenance, (b) Insurance, (c) Rate and taxes and (d) Effluent treatment plant should be allocated on the basis of production have been provided, however the same has been rejected.

EXAMINATION BY AUTHORITY

22. It is noted that post disclosure comments have been filed only by domestic industry in this case. It is also noted that the no new issues/comments have been filed by the domestic industry post disclosure. It is also noted that the Authority has already examined the issues raised by the domestic industry in the disclosure statement and the issues have also been addressed appropriately and does not require any further reconsideration. In view of this, the examination carried out by the Authority regarding NIP re determination and as mentioned in para 10-20 is confirmed.

CONCLUSIONS

23. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties, facts available before the Authority as recorded in this finding and the facts available before the authority in the final finding dated 19.07.2017, the revised NIP is Rs. *** /MT.

RECOMMENDATION

24. Accordingly, the Authority recommended that revised anti-dumping duties be continued to be imposed from the date of issue of notification by the Central Government on imports of Sodium Nitrite falling under chapter 28 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China PR. The anti-dumping duty shall be the amount mention in Column No. 8 of the following table. This anti-dumping duty will remain effective for 5 years from the date of Customs Notification No. 40/2017-Custom (ADD) dated 25.08.2017.

Duty Table

Sl. No.	Sub-heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834.1010	Sodium Nitrite	China PR	China PR	Any	Any	79.58	MT	US\$
2	-Do-	-Do-	China PR	Any Country other than China PR	Any	Any	79.58	MT	US\$
3	-Do-	-Do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	Any	79.58	MT	US\$

FURTHER PROCEDURES

25. An appeal against this notification, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Spl. Secy. & Designated Authority